www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 289 | जौनपुर बुधवार, 10 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

असम में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए–डीआर 60 प्रतिशत होगा

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी, जिसके बाद डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से राज्य भर में आठ लाख से अधिक मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान जुलाई से किया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा, "हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा में अहम भागीदार हैं। उन्हें और सहायता देने के लिए असम कैबिनेट ने डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे यह इस जुलाई से 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।

समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मूल्यवर्धन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मूल्यवर्धन, स्थिरता, निर्यात अवसंरचना और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और देश का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि समुद्री खाद्य क्षेत्र भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में समुद्री उत्पादों के निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र की बढ़ती क्षमता और वैश्विक मांग को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समुद्री खाद्य निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और भारत को वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। कार्यशाला में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) ढांचे, कोल्ड चेन अवसंरचना और समुद्री खाद्य क्षेत्र में निर्यात के नए अवसरों पर व्यापक चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाएं समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रतिभागियों ने निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया।

पीएम मोदी ने कहा- सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण के समर्पित प्रयासों के रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और 'राष्ट्र प्रथम' की अटूट भावना के साथ सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप आज भारत ने विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "हमारी सरकार के पिछले 12 साल भरोसे, विकास और जन–कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ हमने अपने युवाओं, महिलाओं और किसान भाई–बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।" प्रधानमंत्री ने नौ प्रमुख क्षेत्रोंय गरीब कल्याण, नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, स्वास्थ्य, राष्ट्र प्रथम, किसान कल्याण, मिडिल क्लास और विरासत और विकासय के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 81 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 10.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों का जीवन आसान हुआ है। नारी सशक्तीकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन–धन खाते खोले गए हैं। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का अवसर मिला है और 3 करोड़ से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं।

अफवाहों से नहीं चलेगा झूठ का नैरेटिव – सीएम ब्रजेश

लखनऊ, (संवाददाता)। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख राम मंदिर को लेकर अफवाहें फैलाकर झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनकी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है।समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन पर तीखा निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह अफवाहें फैलाकर झूठ गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा प्रमुख ने कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर मुद्दे पर अखिलेश यादव का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है और उनकी सोच श्बाबरवादीश मानसिकता से प्रेरित दिखाई देती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब श्रीराम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन हुआ, तब भी अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अयोध्याधाम में भव्य मंदिर निर्माण का स्वरूप सामने आया, तब भी वह मौन रहे। यहां तक कि प्रभु श्रीराम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक अवसर पर भी उन्होंने स्वागत का एक शब्द तक नहीं कहा। अब वह मंदिर को लेकर भ्रम और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत विश्व में सनातन संस्कृति का वाहक राष्ट्र है ।

पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दो वर्ष पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने 'सेवा' की भावना के साथ शासन–व्यवस्था को नई परिभाषा दी है और विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि 2024 में इसी दिन नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर देश के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था को सेवा–भावना के साथ संचालित किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि "स्वयं से पहले सेवा" के सिद्धांत से प्रेरित इस 12 वर्षीय यात्रा में गरीबों का सशक्तीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती, व्यापक सुधार, तेज बुनियादी ढांचा विकास और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण आयाम शामिल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश के लिए ये 12 वर्ष दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास और राष्ट्र–प्रथम शासन की प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 12 वर्षों को भारत के परिवर्तन, प्रगति और जन–कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा बताया।

बिरसा मुंडा सामाजिक न्याय की खोज में राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे – उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बिरसा मुंडा को भारत के सबसे प्रमुख आदिवासी नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। 1875 में आज के झारखंड में जन्मे बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और आदिवासी समुदायों पर थोपी गई शोषणकारी जमीन नीतियों के खिलाफ ऐतिहासिक 'उलगुलान' या 'महान विद्रोह' का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर मैं सम्मानित 'धरती आबा' को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका जीवन साहस, आत्म–सम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। ऐतिहासिक 'उलगुलान' के माध्यम से उन्होंने दमन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना जगाई और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया।" उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, "यह मेरे लिए गहरे व्यक्तिगत सम्मान की बात है कि मुझे झारखंड के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने के पहले ही दिन और हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पवित्र जन्मस्थान 'उलिहातू' पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला।" उल्लेखनीय है कि अपने आंदोलन के जरिए बिरसा मुंडा ने हजारों आदिवासी लोगों को उनके अधिकारों, पहचान और पारंपरिक जमीन के मालिकाना हक के लिए लड़ने के लिए एकजुट किया। हालांकि उनका आंदोलन मुख्य रूप से छोटानागपुर क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन बिरसा मुंडा की विरासत असम सहित कई राज्यों में भी काफी असरदार है। असम में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी और 'टी ट्राइब' (चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी समुदाय) के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान छोटानागपुर पठार से वहां जाकर बस गए थे।

देश की सीमा सुरक्षा में नया अध्याय- अमित शाह लॉन्च करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) लॉन्च करेंगे। एक अधिकारी ने बयान में कहा, ष्एलपीएमएस एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे लैंड पोर्ट्स के संचालन को एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। यह लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी जानकारी के सुरक्षित तथा रियल–टाइम आदान–प्रदान को संभव बनाता है, जिससे लैंड पोर्ट्स भी एयरपोर्ट और सीपोर्ट पर उपलब्ध आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के समकक्ष हो जाएंगे।ष्आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य तकनीक आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा–पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही में दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर, केंद्रीय गृह मंत्री डाकी (मेघालय) और श्रीमंतपुर (त्रिपुरा) लैंड पोर्ट्स पर विभिन्न हितधारकों के लिए निर्मित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे सीमा क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षा बलों के जवानों और अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए आधारभूत सुविधाएं और मजबूत होंगी।एलपीएमएस की शुरुआत भारत के आधुनिक और टेक्नोलॉजी–बेस्ड स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की ओर बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह व्यापार को आसान बनाने, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और श्2047 तक विकसित भारतश के लक्ष्य पर देश के रणनीतिक फोकस को दिखाता है।बयान में कहा गया है, ष्एक निष्पक्ष और खुले प्लेटफॉर्म के रूप में एलपीएमएस सरकारी एजेंसियों और निजी परिचालकों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा, जिससे देरी कम होगी और परिचालन क्षमता बढ़ेगी।ष्यह प्रणाली कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए एंड–टू–एंड डिजिटल वर्कफ्लो उपलब्ध कराएगी।

बी.के. मुकेश भाई द्वारा की गई अनोखी पहल : रामराज्य संकल्प वृक्ष कोविदार लगाकर नशा-मुक्त अभियान के साथ सनातन धर्म और पर्यावरण संरक्षण को किया जा रहा मजबूत

शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट एवं ब्रह्माकुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र साईं का पूरवा, दर्शन नगर, अयोध्या के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा सराहनीय कार्य

देश की उपासना ब्यूरो

अयोध्या। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू के अधीन संचालित राजयोग सेवा केंद्र साईं का पूरवा, दर्शन नगर के संचालक बी.के. मुकेश भाई एवं शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में रामराज्य संकल्प वृक्ष, जिसे कोविदार वृक्ष के रूप में जाना जाता है, का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, नशा–मुक्त जीवन तथा सनातन धर्म के प्रचार–प्रसार की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस पुनीत अभियान में प्रमुख रूप से इंजीनियर रवि तिवारी जी की तीक्ष्ण बुद्धि एवं सक्रिय सहयोग के साथ श्री चंद्रशेखर तिवारी एवं प्रवीण भाई का भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है। साथ ही ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू के वरिष्ठ भाई बहनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। बताया जाता है कि रामराज्य संकल्प वृक्ष कोविदार, जिसे प्राचीन काल में भगवान श्रीराम के राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में अयोध्या के राजध्वज में स्थान प्राप्त था, त्रेता युग के पश्चात धीरे–धीरे विलुप्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक प्रेरणा एवं सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित दृष्टिकोण के फलस्वरूप इस वृक्ष की पुनः पहचान हुई और इसे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की ध्वज पताका में भी स्थान दिया गया। इसी प्रेरणा से अयोध्या को नशा–मुक्त बनाने तथा सनातन धर्म को सशक्त करने के उद्देश्य से इस कोविदार वृक्ष को जनपद की सभी 963 ग्राम पंचायतों में लगाने का संकल्प लिया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रामराज्य संकल्प अभियान को भी बल मिल सके। देश की उपासना समाचार पत्र एवं डीकेयू लाइव चौनल के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कुमार को जानकारी देते हुए बी.के. मुकेश भाई ने बताया कि वर्ष 2026 में कुल 2000 कोविदार वृक्ष पवित्र व्यक्तियों के पवित्र हाथों एवं पवित्र धन से लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 300 ग्राम पंचायतों में रामराज्य संकल्प वृक्ष कोविदार का वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अगस्त 2026 के अंत तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अयोध्या को नशा–मुक्त बनाना, रामराज्य की अवधारणा को साकार करना तथा सनातन धर्म की स्थापना को और अधिक बल प्रदान करना है। साथ ही, ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर लोगों को आध्यात्मिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ना भी इसका उद्देश्य है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सके। बी.के. मुकेश भाई ने अपने हाथों में रामराज्य संकल्प वृक्ष कोविदार का पौधा दिखाते हुए बताया कि इस अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम राजयोग सेवा केंद्र साईं का पूरवा, दर्शन नगर, अयोध्या से की गई थी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जनपद के प्रमुख स्थलों तथा सभी ग्राम पंचायतों में इस वृक्ष का रोपण कराया जाएगा। इस संबंध में बी.के. मुकेश भाई एवं शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट अयोध्या के पदाधिकारियों ने आम जनमानस से अपील की है कि वे रामराज्य संकल्प वृक्ष कोविदार के वृक्षारोपण अभियान में भागीदार बनें तथा नशा–मुक्त अयोध्या के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। उनका कहना है कि यदि अयोध्या के नागरिक इस अभियान से जुड़ते हैं तो भगवान श्रीराम की पावन नगरी को नशा–मुक्त, पर्यावरण–सुरक्षित एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। यही ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट अयोध्या का मुख्य उद्देश्य है।

उधमपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर बनेगी नई दो–लेन ट्यूब टनल – जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने जम्मू–कश्मीर के उधमपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना की घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर एक नई दो–लेन ट्यूब टनल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बताया। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उधमपुर के लिए यह एक और अच्छी खबर है और नई टनल के निर्माण से चेनानी–नाशरी मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग–44 जम्मू–कश्मीर की जीवनरेखा है और इस मार्ग पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर नई दो–लेन ट्यूब टनल का निर्माण यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह परियोजना केवल स्थानीय निवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आवागमन करने वाले लाखों लोगों के लिए भी लाभदायक साबित होगी। नई टनल बनने के बाद यातायात का दबाव विभाजित होगा।

संपादकीय

सात-सूत्री अपील

सवा दो महीनों तक आर्थिक मजबूती का गैर–जरूरी दिखावा करने के बाद आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सात–सूत्री अपील भारतवासियों से की है। तो आखिर ये नौबत आ पहुंची। प्रधानमंत्री को डॉलर और तेल– गैस बचाने के लिए आम नागरिकों से अपील करनी पड़ी है। सवा दो महीनों तक आर्थिक मजबूती का गैर–जरूरी दिखावा करने (मुमकिन है जारी चुनाव के कारण किया गया हो) के बाद अब नरेंद्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सात–सूत्री अपील भारतवासियों से की है। कहा है कि ऊर्जा बचाने के लिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर पेट्रोल– डीजल की खपत घटानी चाहिए, और रसोई ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करनी चाहिए। विदेशी मुद्रा खर्च ना हो, इसके लिए साल भर उन्हें सोना नहीं खरीदना चाहिए, स्वदेशी उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और विदेश यात्रा से बचना चाहिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिए कुदरती खेती की ओर जाना चाहिए। ये बातें ऊर्जा, डॉलर, और उर्वरकों की संभावित किल्लत की ओर इशारा करती हैं। ईरान युद्ध ने विश्व ऊर्जा बाजार के स्वरूप को फिलहाल बदल दिया है। इसकी मार उन तमाम देशों पर पड़ी है, जिनके पास अपना ऊर्जा स्रोत नहीं है और अच्छे दौर में रणनीतिक भंडार बना लेने की बात जिनके दिमाग में नहीं आई। फिलहाल, बाजार में कच्चा तेल उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए (फरवरी की तुलना में) सवा से डेढ़ गुनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव तेजी से बढ़ा है। इसी बीच विदेशी निवेशकों की भारत से पैसा निकालने के तेज होती गई रफ्तार और रुपये की कीमत में आई भारी गिरावट ने संकट और बढ़ा दिया है। उधर पश्चिम एशिया से घटे आयात के कारण उर्वरक में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का अभाव हो गया है, जिससे खाद्य संकट की आशंकाएं गहराई हैं। ऐसे में कई देश पहले ही ऊर्जा एवं डॉलर बचाने के उपाय अपना चुके हैं। मगर भारत में बात तब शुरू हुई है, जब पानी सिर तक पहुंच गया है। तब भी बात सिर्फ नागरिकों तक है। जो भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर का अमेरिका में कर रही हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जगाने का आह्वान अभी नहीं किया गया है।

पीएम स्वनिधि गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर

पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा, इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से, अब तक 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है जो अपनी आजीविका को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। भारत के रेहड़ी–पटरी वालों की बदलती कहानी किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में सब्जी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ्तर के बाहर चाय बेचने वालाकृये भारतीय शहरों में आम नजारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाला और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाला मोची भी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी के लिए उतने ही जरूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी–पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों और आस–पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफायती सामान और जरूरी सेवाएं देते हैं। हालांकि, औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए, जून 2020 में श्प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधिश (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की गई। यह अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्त (माइक्रो–क्रेडिट) पहल थी, जो रेहड़ी–पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी–पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान देना था। आज, पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है, जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में जबरदस्त तरक्की की है। 75.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण लिए हैं, जिनकी कुल रकम 17,800 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर, उन्होंने लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपये के 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपये भी मिले हैं। इन मजबूत उपलब्धियों और महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए, इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कार्यशील पूंजी ऋणरू बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋण, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के साथ, तीन चरणों में दिए जाते हैं। जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, वे 30,000 रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई –लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं। डिजिटल प्रक्रिया को अपनानारू डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रीट वेंडरों को खुदराध्थोक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। स्वनिधि से समृद्धि (एसएसएस)रू लाभार्थियों और उनके परिवारों का सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, ताकि उन्हें आठ चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके और एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाया जा सके। विक्रेताओं को एफएसएसएआई के सहयोग से वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, और खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना का असर पीएम स्वनिधि का स्वतंत्र असर मूल्यांकन 2023 और 2025 में किया गया था। इन अध्ययनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार सामने आए। इस योजना ने देश भर के विक्रेताओं के लिए व्यापार की स्थिरता को मजबूत किया है और उनकी आमदनी में सुधार किया है। लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया। लगभग 30 प्रतिशत लोगों ने बाद में स्वनिधि ऋणों के अलावा अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया।

भारतीय नौसेना के बीचोंबीच होगा भारत का सबसे बड़ा सैन्य किला

नीरज

मोदी सरकार ने हिंद महासागर में ऐसा दांव चला है, जिसने चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला

भारत का नया सैन्य और आर्थिक हब अब दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी बन चुका है। जिस समुद्री रास्ते से दुनिया का सबसे बड़ा तेल और व्यापार गुजरता है, वहां अब भारत अपनी ताकत का स्थायी पहरा बैठाने जा रहा है। साफ है कि मोदी सरकार हिंद महासागर में भारत को सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि सबसे प्रभावशाली ताकत बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जिस हरित क्षेत्र हवाई अड्डे को मंजूरी दी थी, वह अगले पांच वर्षों में तैयार होने की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हवाई अड्डा भारतीय नौसेना के संचालन नियंत्रण में रहेगा। यानी यह केवल नागरिक उड़ानों का केंद्र नहीं होगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की सैन्य शक्ति का नया अग्रिम मोर्चा बनेगा। यह दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा भारत की समुद्री निगरानी क्षमता, सैन्य पहुंच और त्वरित कार्रवाई की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। हम आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार की यह परियोजना चार बड़े स्तंभों पर आधारित है। इनमें अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, आधुनिक नगर, ऊर्जा संयंत्र और नौसैनिक हवाई अड्डा शामिल हैं। यह पूरा ढांचा भारत को उस समुद्री क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति देगा, जहां से दुनिया के दो तिहाई तेल व्यापार और आधा कंटेनर यातायात गुजरता है। ग्रेट निकोबार केवल चालीस किलोमीटर दूर स्थित है उस सिक्स डिग्री चौनल से, जो अदन की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले समुद्री व्यापार मार्ग का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। यही वह इलाका है जहां चीन लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में कई बाहरी ताकतें आर्थिक और सैन्य दबदबा बनाने में जुटी हैं। ऐसे में मोदी सरकार का यह कदम भारत को दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में निर्णायक बढ़त देगा। यानि अब भारत इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा साझेदार और संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाली ताकत के रूप में उभरेगा। रक्षा सूत्रों का साफ कहना है कि यह परियोजना तीस वर्ष पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों की सुस्ती और दूरदृष्टि की कमी के कारण भारत ने बहुमूल्य समय गंवा दिया। अब मोदी सरकार उस रणनीतिक भूल को सुधार रही है। यह परियोजना भारत को अपने सैन्य संसाधनों की तेज आवाजाही, अग्रिम रसद आपूर्ति और समुद्री निगरानी में अभूतपूर्व क्षमता देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार के आसपास समुद्र में विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ऐतिहासिक साबित होगी। यानी यह केवल सैन्य ताकत का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी बड़ा आधार बनेगी। साथ ही मोदी सरकार ने उन आलोचनाओं को भी करारा जवाब दिया है, जिनमें इस परियोजना को केवल व्यावसायिक योजना बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। रक्षा सूत्रों ने साफ कहा है कि इसे केवल कारोबारी परियोजना कहना भौगोलिक अज्ञानता का प्रमाण है। यह परियोजना सामरिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत के भविष्य की धुरी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाएं पूरी पारदर्शिता और विधिवत ठेका प्रक्रिया के तहत संचालित की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि परियोजना के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से काम चल रहा है। कंटेनर बंदरगाह के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर परियोजना पर व्यय वित्त समिति की बैठक हो चुकी है, जबकि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर तेजी से अमल भी कर रही है। इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर उठे सवालों पर भी सरकार ने तथ्यात्मक जवाब दिया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन के अनुसार पूरे द्वीप के केवल 166.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि 81.74 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन और जनजातीय संरक्षण क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित रहेगा। वन क्षेत्र के उपयोग में भी आधे से अधिक हिस्से को हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जहां पेड़ों की कटाई नहीं होगी। इसके साथ ही वन्यजीवों, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव संरक्षण के लिए तीस वर्षों में दो हजार दो सौ बीस करोड़ रुपये से अधिक का विशेष संरक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। लेदरबैक कछुए, निकोबार मेगापोड और मगरमच्छों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि ग्रेट निकोबार परियोजना मोदी सरकार का केवल विकास अभियान नहीं, बल्कि भारत की समुद्री शक्ति का नया शंखनाद है। यह वह मास्टरस्ट्रोक है जो आने वाले दशकों में हिंद महासागर की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। भारत अब अपने समुद्री हितों की रक्षा केवल तटों से नहीं करेगा, बल्कि समुद्र के बीचोंबीच अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराएगा।

आखिर इंडिया गठबंधन की बैठक के राजनीतिक मायने हैं

कमलेश

विगत दो–तीन वर्षों में कांग्रेस की सियासी विसात पर अपना अपना–सबकुछ लुटा–पिटा देने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की जो ष्नई दिल्ली बैठकष हुई, उसके राजनीतिक मायने कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए। क्योंकि इस बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज ध्यान से सुनी गई और उनके नेतृत्व को तथा उनकी पार्टी को गाहे–बगाहे चुनौती देने वाले क्षेत्रीय दलों के सुरमा भोपाली नेता दबी जुबान में अपनी भावना प्रकट करने को अभिशप्त हुए। खासकर नेशनल कांफ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को छोड़कर। इसलिए यह बैठक केवल एक नियमित विपक्षी बैठक तक सीमित नहीं रही, क्योंकि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब कई सहयोगी दलों और कांग्रेस के बीच मतभेदों की बढ़ती–घटती खबरें सामने आई थीं, इसलिए इसके संदेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, 8 जून को इंडियागठबंधन की बैठक में लगभग 23 दलों के राजनेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाने और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में लगभग 23 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिनमें मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले के अलावा प्रमुख वामपंथी दलों के अनेक नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार की नीतियों, विदेश नीति और मतदाता सूची पुनरीक्षण (ैप्त्) से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जबकि विपक्षी दलों ने संसद और सड़क दोनों स्तरों पर समन्वित आंदोलन चलाने तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रुख अपनाने पर चर्चा की। साथ ही, 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी, विपक्षी एकता और गठबंधन के भविष्य की दिशा भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही। बैठक के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल पर मंथन हुआ। फिर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनाई गई और संसद में विपक्षी दलों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों के बीच तालमेल और राजनीतिक सहयोग होने की पुष्टि की गई। वहीं, इस बैठक की कतिपय चुनौतियां भी सामने आईं, क्योंकि जहां तमिलनाडु में सत्ता से बेदखल हुई DMK ने कांग्रेस से नाराजगी होने के चलते इस बैठक से दूरी बनाई, जिससे गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज रही। वहीं, आप के सुप्रीमो अरबिंद केजरीवाल की अनुपस्थिति भी चर्चा में रही। जबकि कुछ अन्य सहयोगी दलों की भूमिका और भागीदारी को लेकर भी सवाल बने रहे। जहां तक इंडिया गठबंधन की इस बहुप्रतीक्षित बैठक के राजनीतिक मायने की बात है तो यह बैठक लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण गैर–संसदीय बैठकों में से एक मानी जा रही है। जिसके माध्यम से विपक्ष ने संदेश देने की कोशिश की कि मतभेदों के बावजूद भाजपा के खिलाफ साझा मंच अभी कायम है। वहीं, भाजपा ने DMK की अनुपस्थिति और अन्य अंतर्विरोधों को लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए हैं। इस बैठक के सबसे बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।– पहला, INDIA गठबंधन अभी समाप्त नहीं हुआ है सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि तमाम मतभेदों, चुनावी झटकों और सहयोगी दलों की नाराजगी के बावजूद विपक्षी दलों ने एक साझा मंच बनाए रखने का निर्णय लिया। 23 दलों की भागीदारी ने कांग्रेस को यह कहने का अवसर दिया कि गठबंधन अभी भी प्रासंगिक है। दूसरा, 2029 की तैयारी अभी से शुरू हो गईरू बैठक का प्रमुख उद्देश्य केवल वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव के लिए दीर्घकालिक रणनीति

तैयार करना भी था। विपक्ष भाजपा के विरुद्ध एक व्यापक राष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में दिखा। तीसरा, कांग्रेस फिर से समन्वयक की भूमिका में बैठक से यह संकेत मिला कि कांग्रेस गठबंधन की धुरी बनी रहना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी एकता पर जोर दिया और केंद्र सरकार के विरुद्ध साझा संघर्ष का आह्वान किया। चौथा, गठबंधन की कमजोरी भी उजागर हुई दूर रहना बताता है कि विपक्षी एकता अभी भी कई अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस बैठक का बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजद नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय मंच मिला। बैठक में मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि वे केवल बिहार तक सीमित नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वहीं, बिहार चुनाव में विपक्षी एकता का संदेशभी गया। ऐसे में यदि कांग्रेस, राजद और वाम दल तालमेल बनाए रखते हैं तो बिहार में छक। के खिलाफ विपक्षी चुनौती अपेक्षाकृत मजबूत रह सकती है। वहीं, जाति और सामाजिक न्याय की राजनीति को भी बल मिला। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय, जातीय गणना और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को साथ उठाते रहे हैं। बैठक से संकेत मिला कि यह विपक्ष का प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बना रह सकता है। जहां तक 2029 के लोकसभा चुनाव पर संभावित प्रभाव की बात है तो इसका सकारात्मक पक्ष यह रहा कि भाजपा के विरुद्ध एक साझा राष्ट्रीय मंच बना रहता है। वहीं, संसदीय मुद्दों पर समन्वय बढ़ सकता है। साथ ही क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच संवाद कायम रहने की संभावना बनी रहती है। वहीं, जहां तक चुनौतियों की बात है तो सीट बंटवारा सबसे बड़ी समस्या रहेगा। क्योंकि कई राज्यों में सहयोगी दल एक–दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। वहीं, क्डझ और जैसी पार्टियों की दूरी गठबंधन की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह कहा जा सकता है कि इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश यह रहा कि प्छक्प्। गठबंधन ने अपने अस्तित्व और प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने की कोशिश की। लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपने भीतर की एकता बनाए रखना है। बिहार में इसका तात्कालिक लाभ महागठबंधन को मिल सकता है, जबकि 2029 के लिए यह बैठक विपक्षी पुनर्गठन की शुरुआत मानी जा सकती हैकृहालांकि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सहयोगी दल भविष्य में अपने मतभेद कितनी प्रभावी ढंग से सुलझा पाते हैं।

सहभागी जल बजटिंग के जरिए समुदायों का सशक्तीकरण

गोपाल

भारत में जल संकट केवल संसाधनों की कमी का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या, असमान वर्षा वितरण, भूजल दोहन और जलवायु परिवर्तन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे समय में जल बजटिंग एक प्रभावी और सहभागी समाधान के रूप में उभरकर सामने आई है, जो समुदायों को जल संसाधनों के वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग के लिए सक्षम बना रही है। जल शक्ति मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित पहलें यह दर्शाती हैं कि यदि स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में सहभागी बनाया जाए तो जल संकट का दीर्घकालिक समाधान संभव है। अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल मिशन, जलयुक्त शिवर अभियान और राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इसके सफल उदाहरण हैं। जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव केंद्रीय जल आयोग के अध्ययन के अनुसार भारत में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 3880 अरब घन मीटर वर्षा होती है। प्राकृतिक क्षति और वाष्पीकरण के बाद देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 1999 अरब घन मीटर आंकी गई है। हालांकि, बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी और 11.6 प्रतिशत पशुधन भारत में है, जबकि जल संसाधन सीमित हैं। ग्रामीण भारत में उपलब्ध जल का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि में उपयोग होता है। ऐसे में भूजल स्तर में गिरावट और जल संकट की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जल बजटिंग का अर्थ किसी गांव, ब्लॉक, जलग्रहण क्षेत्र या जिले में उपलब्ध जल और उसकी मांग का वैज्ञानिक आकलन करना है। इसमें वर्षा, भूजल पुनर्भरण, सतही जल, बहाव, वाष्पीकरण और विभिन्न उपयोगों की जल मांग को शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि जल के स्रोतों, मौसमी बदलावों और मानव गतिविधियों के प्रभाव को समझने का माध्यम भी है। इसके आधार पर कृषि, घरेलू उपयोग, पशुपालन और अन्य गतिविधियों के लिए संतुलित जल आवंटन संभव हो पाता है। कृषि और पशुपालन में सहायक राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग के अनुसार वर्ष 2050 तक सिंचाई के लिए पानी की मांग 807 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। ऐसे में जल बजटिंग किसानों को स्थानीय जल उपलब्धता के अनुरूप फसल चयन और सिंचाई पद्धति अपनाने में मदद करती है। नाबार्ड समर्थित पहलों से यह स्पष्ट हुआ है कि जल उपलब्धता के अनुसार फसल योजना बनाने से जोखिम कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग और फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता में सुधार लाया जा रहा है। भारत में पशुधन की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या बढ़कर लगभग 53.6 करोड़ हो गई। इससे पशुओं के लिए पानी और चारे की मांग भी बढ़ी है। जल बजटिंग इन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर समग्र जल प्रबंधन सुनिश्चित करती है। अटल भूजल योजना से बदली तस्वीर वर्ष 2019 में शुरू की गई अटल भूजल योजना भूजल संकट वाले सात राज्यों के 229 ब्लॉकों में लागू की गई। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट तैयार किए जा रहे हैं और स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण गतिविधियों से जोड़ा गया है। मार्च 2026 तक लगभग 81,700 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जा चुका है। योजना के तहत 8,203 जल बजट तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 1.25 लाख से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 229 में से 180 ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि सहभागी जल प्रबंधन किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हिवरे बाजार बना प्रेरणा मॉडल हिवरे बाजार गांव आज देश में सामुदायिक जल प्रबंधन का सफल उदाहरण बन चुका है। कभी सूखे और जल संकट से जूझने वाला यह गांव अब जल आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया है। ग्राम सभा स्तर पर वार्षिक जल बजट तैयार कर किसानों को उपलब्ध पानी के अनुसार फसल चयन के लिए प्रेरित किया गया। भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए गहरे बोरवेल पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्षा जल संचयन और जलग्रहण विकास जैसे उपायों ने गांव की तस्वीर बदल दी। इस मॉडल से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सूखा–रोधी रणनीति में जल बजटिंग को शामिल किया है और हर वर्ष हजारों गांवों को जल सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान महिलाओं को जल संरक्षण और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका दे रहा है। स्वयं सहायता समूहों और ग्राम जल समितियों के माध्यम से महिलाएं जल शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं।

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1,600 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। महिला नेतृत्व वाली समितियां गांवों में जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान चला रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट आधारित जल संरक्षण मॉडल लागू किया गया। इसमें वर्षा जल, भूजल, मिट्टी की नमी और सतही जल के संरक्षण पर जोर दिया गया। ग्राम सभा स्तर पर जल बजटिंग को संस्थागत रूप देने से समुदाय स्वयं जल उपलब्धता का आकलन कर विभिन्न जरूरतों के लिए जल आवंटन तय कर रहे हैं। इस पहल से भूजल स्तर में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और लाखों लोगों तथा पशुओं के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। तकनीक से आसान हुआ जल प्रबंधन वरुणी वेब एप्लीकेशन जैसी डिजिटल तकनीकें जल बजटिंग को और अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बना रही हैं। यह प्लेटफॉर्म वर्षा, फसल पैटर्न, भूमि उपयोग और जनसंख्या से संबंधित सरकारी डेटा का उपयोग कर ब्लॉक स्तर पर जल बजट तैयार करता है। इस तकनीक की सहायता से स्थानीय प्रशासन जल की कमी या अधिकता का सटीक आकलन कर सकता है और आवश्यक कदम उठा सकता है। इससे जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा मिल रहा है। जलयुक्त शिवर अभियान की सफलता महाराष्ट्र सरकार का जलयुक्त शिवर अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और ग्राम स्तर पर जल बजटिंग को बढ़ावा दिया गया। अभियान के परिणामस्वरूप 11 हजार से अधिक गांवों को सूखा मुक्त घोषित किया गया है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में 1.5 से 2 मीटर तक वृद्धि दर्ज की गई और कृषि उत्पादकता में 30 से 50 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। जल संकट से निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समुदाय आधारित, डेटा–आधारित और सहभागी दृष्टिकोण आवश्यक है। जल बजटिंग गांवों को अपनी जल आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है।

संक्षिप्त खबरें

राजधानी में दिन में पड़ी झुलसाने वाली गर्मी, रात में बूंदाबांदी, आज भी रहेंगे लू जैसे हालात

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में सोमवार को तपिश और गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। दोपहर में अचानक बादलों की आवाजाही बढ़ी और उमस भरी गर्मी ने सिर उठाया लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छंट गए। इसके बाद तल्ख धूप के साथ झुलसाने वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई। हालांकि, देर रात फिर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। धूप की तल्खी और गर्म हवाओं से लू जैसी परिस्थितियां बनने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 11 जून से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से राजधानी में बुधवार को देर सवेर बूंदाबांदी की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की बढ़त के साथ 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

जो पति को पतन से बचा ले, वही पत्नी कहलाने योग्य – रामभद्राचार्य

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय संस्कृति में वाइफ और बीवी नहीं होती, यहां धर्मपत्नी होती है। जो पति को पतन से बचा ले, वही पत्नी कहलाने योग्य है। यह बात सोमवार को जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में चल रही कथा के आठवें दिन कही। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान सनातन का मूल मंत्र है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव का भी विरोध हुआ था, जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाए तो कम है। परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने भगवान श्रीराम के वनवास काल में आदिवासियों, गिरिवासियों एवं शबरी से मिलन के प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने ऋषि शरभंग प्रसंग का उल्लेख करते हुए नवधा भक्ति के छठे स्वरूप वंदन भक्ति की विस्तृत व्याख्या की। इस दौरान उन्होंने भक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दीं, जिस पर भक्त झूमते नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र चौधरी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

खुनखुन कॉलेज में सभागार का लोकार्पण

लखनऊ, (संवाददाता)। खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में नए सभागार का लोकार्पण सोमवार को राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने किया। यह सभागार उनकी सांसद निधि से निर्मित हुआ है जिसे उन्होंने अपने पिता केदारनाथ शर्मा को समर्पित किया। उन्होंने अपने पिता से जुड़ी यादें साझा कीं। दिनेश शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। लुआक्टा अध्यक्ष मनोज पांडेय और प्राचार्या अंशु केडिया के अलावा चौक काली वार्ड पार्षद अनुराग मिश्रा और महाविद्यालय प्रबंधक उत्कर्ष अग्रवाल भी मौजूद रहे।

केजीएमयू के विभागों में दवाओं की मांग 30 से 40 प्रतिशत घटी

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में करोड़ों रुपये के कथित दवा घोटाला सामने के बाद दवाओं की खरीद और मांग घट गई है। जांच शुरू होने के बाद यूरोलॉजी विभाग ही नहीं, बल्कि मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग, कैंसर और अन्य विभागों में भी दवाओं की मांग में 30 से 40 प्रतिशत तक कमी आई है। पहले जहां वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए नियमित रूप से बड़ी मात्रा में दवाओं का इंडेंट भेजा जाता था। वहीं अब डॉक्टर जरूरत का आकलन करने के बाद ही दवाओं की मांग कर रहे हैं। कई डॉक्टर महंगी दवाएं लिखने से भी परहेज कर रहे हैं। इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, प्रोटीन, आयरन के महंगे इंजेक्शन शामिल हैं। दवा इंडेंट से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को लेकर भी डॉक्टर सतर्कता बरत रहे हैं। केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के मुताबिक, दवाओं की खपत और मांग में पिछले कुछ दिनों से कमी आई है।

माल क्षेत्र में पत्नी की हत्या, आरोपी पति हिरासत में फॉरेंसिक जांच जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना माल क्षेत्र के आजाद नगर में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर दिए जाने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना माल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।प्रारंभिक जांच में पता चला कि आजाद नगर निवासी लगभग 55 वर्षीय जितेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह ने अपनी पत्नी मोनिका सिंह (उम्र लगभग 47 वर्ष) पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका का शव घर के एक कमरे से बरामद किया गया।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि मामले की हर पहलू से जांच की जा सके।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया।

दुबग्गा क्षेत्र के दबंग व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई, 06 माह के लिए जिला बदर का आदेश जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना दुबग्गा क्षेत्र के एक मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम–1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा आरोपी को 06 माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश पारित किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई संस्थित वाद संख्या 41(09)/2026 के अंतर्गत की गई, जिसकी सुनवाई न्यायालय पुलिस आयुक्त लखनऊ में हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया, जिसके बाद राज्य की ओर से उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह ने कड़े तर्क प्रस्तुत करते हुए ।

कायस्थ महासभा 7235 का आईटी सेल पूरे देश में होगा गठित : सुबीर सेन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 7235 भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख सुबीर सेन का जौनपुर आगमन पर कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। बाजिदपुर स्थित जिला उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव 'बबलू' के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में कायस्थ महासभा 7235 के आईटी सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज संगठन की पहचान देश के कोने–कोने तक पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। सदस्यता निःशुल्क रखकर समाज को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद श्रीवास्तव 'दीनू' ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया जा चुका है तथा शेष जिलों में भी जल्द नियुक्तियां कर संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ महासभा समाज के हितों की रक्षा और उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. उमाकांत श्रीवास्तव एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय वर्मा 'अज्जू' ने कहा कि कायस्थ समाज ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और आगे भी समाज व राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाल सरन श्रीवास्तव एवं दयाशंकर निगम ने कहा कि जौनपुर का कायस्थ समाज पूरी तरह एकजुट है और समाज के हितों के लिए हमेशा संगठित होकर कार्य करता रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव 'दीपक' तथा राष्ट्रीय संरक्षक उमेश श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कायस्थ महासभा 7235 देश के अग्रणी कायस्थ संगठनों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुबीर सेन का जौनपुर आगमन जिले के लिए गौरव का विषय है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। अंत में अखिलेश श्रीवास्तव 'बबलू' ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, समाजसेवी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कायस्थ महासभा 7235 का आईटी सेल पूरे देश में होगा गठित – सुबीर सेन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 7235 भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख सुबीर सेन का जौनपुर आगमन पर कायस्थ समाज के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। बाजिदपुर स्थित जिला उपाध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव 'बबलू' के आवास पर आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में कायस्थ महासभा 7235 के आईटी सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज संगठन की पहचान देश के कोने–कोने तक पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। सदस्यता निःशुल्क रखकर समाज को एकजुट करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद श्रीवास्तव 'दीनू' ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया जा चुका है तथा शेष जिलों में भी जल्द नियुक्तियां कर संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ महासभा समाज के हितों की रक्षा और उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. उमाकांत श्रीवास्तव एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री अजय वर्मा 'अज्जू' ने कहा कि कायस्थ समाज ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और आगे भी समाज व राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष दयाल सरन श्रीवास्तव एवं दयाशंकर निगम ने कहा कि जौनपुर का कायस्थ समाज पूरी तरह एकजुट है और समाज के हितों के लिए हमेशा संगठित होकर कार्य करता रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव 'दीपक' तथा राष्ट्रीय संरक्षक उमेश श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कायस्थ महासभा 7235 देश के अग्रणी कायस्थ संगठनों में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुबीर सेन का जौनपुर आगमन जिले के लिए गौरव का विषय है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। अंत में अखिलेश श्रीवास्तव 'बबलू' ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, समाजसेवी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जौनपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी अलर्ट, चलाया विशेष सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर जौनपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए विशेष चेकिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया। जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गौड़ के नेतृत्व में स्टेशन परिसर, प्लेटफार्मों और यात्री प्रतीक्षालयों में सघन निगरानी की गई तथा परीक्षार्थियों और यात्रियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जौनपुर पहुंचे हैं। इसे देखते हुए जीआरपी ने स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरतते हुए संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखी। अभियान के दौरान परीक्षार्थियों को अपने मोबाइल फोन, दस्तावेज और सामान की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गौड़ ने बताया कि भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन परिसर में लगातार गश्त की जा रही है और आने–जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीआरपी का उद्देश्य यात्रियों और परीक्षार्थियों को सुरक्षित, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान स्टेशन पर ठहरे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बाहर से आए परीक्षार्थियों को आवश्यक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अभियान के दौरान जीआरपी जवानों ने प्लेटफार्मों पर पहुंचकर यात्रियों और अभ्यर्थियों से संवाद किया तथा उन्हें जेबकतरों, ठगों और अन्य असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की सलाह दी। जीआरपी की इस पहल को यात्रियों और अभ्यर्थियों ने सराहा। भर्ती परीक्षा के दौरान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गौरी शंकर धाम में विशेष पूजा-अर्चना, सांसद सीमा द्विवेदी ने की देश की समृद्धि की कामना

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को जौनपुर के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में विशेष पूजा–अर्चना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं विधि–विधान से पूजा कर देश की सुख–समृद्धि तथा प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और हर–हर महादेव के जयघोष के बीच आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पार्टी कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूजा–अर्चना के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और अनेक ऐतिहासिक निर्णयों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और देश आत्मनिर्भरता एवं विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांसद ने कहा कि यह आयोजन केवल उपलब्धियों के उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रति समर्पित नेतृत्व के प्रति जनता की आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जौनपुर में तीन दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षा में 56880 में 15271 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा 416 09 अभ्यर्थी हुए शामिल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर में तीन दिवसीय आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा बुधवार को 21 केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न हुई. पुलिस भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू हुई थी , तीन दिन चलने वाली परीक्षा 6 पालियो में पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गयी थी.इस तीन दिन की परीक्षा में 58880 अभ्यर्थियों में से 15271 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी और 416 09 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए है। पहले दिन सोमवार की पहली पाली में 9876 अभ्यर्थियों में से 2641 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी और 6839 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दुसरे पाली में 9480 अभ्यर्थियों में से 2641 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी 6839 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दुसरे दिन मंगलवार की पहली पाली में 9480 में से 2575 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी 6905 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दूसरी पाली में 9480 अभ्यर्थी में से 2420 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी 7060 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। आखिरी दिन बुधवार की पहली पाली में 9480 अभ्यर्थियो में से 2504 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी 6976 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी पाली में 9480 अभ्यर्थियों में से 2490 अभ्यर्थियो ने परीक्षा छोड़ी और 6990 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा देकर निकलने के बाद अभ्यर्थी आपस में प्रश्नपत्र के स्तर पर चर्चा करते रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र काफी कठिन था। हिंदी साहित्य, गणित और तर्क शक्ति के प्रश्न काफी उलझाने वाले थे। वहीं, समय प्रबंधन भी चुनौतीपूर्ण रहा। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तरों और प्रश्नपत्र को लेकर चर्चा करते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों का कहना था कि हिंदी में साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्नों में काफी समय लगा। गणित में ज्यामिती और प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों भी कठिन रहे। समसामयिक घटनाक्रम से जुड़े कई प्रश्न सामान्य तैयारी के दायरे से अलग थे। इससे उन्हें हल करने में परेशानी हुई। इसके अलावा अक्षरों के समूह पैटर्न की पहचान करने वाले कुछ प्रश्न भी कठिन साबित हुए। मिर्जापुर के सुनील गौतम, ने बताया कि तर्क शक्ति के प्रश्न काफी घुमावदार थे। विशेष रूप से वर्णमाला, दिशा व दूरी, वेन आरेख और सांकेतिक भाषा से जुड़े प्रश्नों ने उलझाया। समसामयिक घटनाक्रम की बेहतर तैयारी करने वालों को लाभ मिला होगा। मऊ से विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पेपर काफी कठिन था। हिंदी साहित्य और समसामयिक घटनाक्रम से जुड़े प्रश्नों ने काफी समय लिया। गणित के तालिका से जुड़े प्रश्न भी अपेक्षाकृत कठिन थे। परीक्षा में समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण रहा है। बलिया के सुरेश यादव ने बताया कि गणित की अच्छी तैयारी करने वालों के लिए पेपर आसान रहा। समसामयिक घटनाक्रम और गणित दोनों ही विषय चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। इस बकर चयन सूची का स्तर बढ़ने की संभावना है।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन पहली पाली में 2,504 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की लिखित परीक्षा के अंतिम दिन बुधवार को पहली पाली शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न हुई। पहली पाली में कुल 9,480 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 6,976 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,504 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

जनपद में यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है। प्रतिदिन दो पालियों में होने वाली परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए जिले में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं, जहां छह पालियों में कुल 56,880 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निगरानी व्यवस्था के तहत 21 केंद्र व्यवस्थापक, 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 21 स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित लगभग 1,200 कार्मिकों की तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं तथा प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार पहली पाली की परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कहीं से किसी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।

दूल्हे आजाद बिंद की हत्या और गाजीपुर में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जाँच की माँग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय मानव समाज पार्टी ने आजाद बिंद की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से दर्जनों कार्यकर्ताओ ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौपा है। संगठन ने कहा कि जौनपुर में दूल्हे आजाद बिंद की हत्या और गाजीपुर में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जाँच की जाए। जौनपुर में 1 मई 2026 को बारात ले जा रहे दूल्हे आजाद बिंद की हत्या कर दी गई थी। घटना के काफी समय बाद भी प्रशासन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहा है। पार्टी ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने और फरार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। गाजीपुर में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित परिवार और समाज ने पुलिस की कार्यशैली और एनकाउंटर की टाइमिंग पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। पार्टी का कहना है कि जब संविधान में आत्मसमर्पण और निष्पक्ष मुकदमे की व्यवस्था है, तो ऐसी कार्रवाई संदेह पैदा करती है। भारतीय मानव समाज पार्टी ने अपनी मुख्य मांगों में जौनपुर हत्याकांड के फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात कही है। इसके साथ ही, गाजीपुर पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है। पार्टी ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान करने की भी अपील की है। पार्टी ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने के नाते इन मामलों का संज्ञान लें। उनसे राज्य सरकार को उचित कदम उठाने के निर्देश जारी करने का विनम्र निवेदन किया गया है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और जनता का भरोसा बहाल हो।

पांच महीने में 1.31 लाख वाहन बिके, हर महीने टूट रहे बिक्री के रिकॉर्ड

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 1.31 लाख से अधिक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन (प्योर ईवी) बिके हैं। यदि यही रफ्तार जारी रही तो इस साल बिक्री तीन लाख से ज्यादा होगी, जो पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र और परिवहन विभाग के अनुसार, जनवरी से मई 2026 के बीच 131653 शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। यह संख्या वर्ष 2025 की कुल बिक्री (211574) का लगभग 62 फीसदी है।

उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग चारु चौधरी ने किया जिला महिला चिकित्सालय के निरीक्षण मे मिली खामिया

अयोध्या। उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग चारु चौधरी ने जिला महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय परिसर में जहां कई वार्डों में कमिया नजर आई वही बच्चा वार्ड में भर्ती एक महिला के पास से चिकित्सक द्वारा लिखी हुई बाहर की दवा से संबंधित पर्ची भी मिली।वही उक्त महिला मरीज के बेड पर बाहर की लिखी हुई दवा भी पाई गई। उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग चौधरी चारु चौधरी द्वारा पूछे जाने पर महिला मरीज ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा उनके तीमारदारों से बाहर से दवा मंगाई जा रही है।जिस पर निरीक्षण करने आई चारु चौधरी काफी नाराज हुई।उन्होंने वहां पर मौजूद सीएमएस डॉक्टर विभा कुमारी सहित अन्य मौजूद चिकित्सकों को फटकार लगाई।इसके अलावा उन्हें जिला महिला चिकित्सालय के कई वार्डो के साथ–साथ परिसर में गंदगी भी दिखाई दी जिसको भी लेकर उन्होंने वहां पर मौजूद चिकित्सा अधिकारियों को जमकर फटकारा।इस मौके पर वहां पर मौजूद मरीजों के तीमारदारों ने उनसे शिकायत भी किया कि यहां पर चिकित्सकों द्वारा तथा जिला महिला चिकित्सालय में सक्रिय दलालों द्वारा बाहर की महंगी दवाई लाने को मजबूर करते हैं।निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों से कहा कि अगर कोई भी चिकित्सक बाहर की दवा लगता है तो इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करें।

स्टाफ की कमी से शहर के आधे इलाकों में रही बिजली गुल

अयोध्या। शहर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्ले व कालोनियां बिजली न रहने के चलते रात भर अंधेरे में डूबी रही।जिसके चलते कुछ ही घंटे बाद इनवर्टर भी जवाब दे गया।लोगों को इस भीषण गर्मी में रात भर जागकर बिताना पड़ा।राठहवेली,अश्वनीपुरम कालोनी,इमामबाड़ा कश्मीरी मोहल्ला, वजीरगंज हैदरगंज सहित कई मोहल्लों में रात भर विद्युत आपूर्ति बाधित रही।इस गंभीर समस्या पर सांसद प्रतिनिधि हामिद जाफर मीसम ने कहा कि चौक बिजली घर पर स्टाफ को फोन करने पर सही जानकारी नहीं दे पाते है।रात को एसडीओ को फोन किया तो सुबह चार बजे एक लाइन मैंन और दो सीढ़ी वाले भेजे लेकिन वो भी राहत देने का काम नहीं कर पाए।सांसद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ रात की ड्यूटी एक लाइनमैन के भरोसे है और दिन में 2 लाइनमैन भरोसे है।उन्होंने बताया कि पूरी एबीसी जल गयी है अफसर आराम से सो रहे हैं जनता सड़क पर है।एबीसी जलने से राठहवेली इमामबाड़ा आंशिक लाइट पूरी रात बंद रही।

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश

अयोध्या कोतवाली अयोध्या पुलिस ने अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन चोरी करने वाले दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफास किया।पुलिस में उनके पास से चोरी के चार मोटर साइकिल भी बरामद किया।इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिवाकान्त तिवारी उर्फ वीरु पुत्र ओंकार नाथ निवासी सोनी हरलाल थाना को0नगर जिला गोण्डा व महेश तिवारी पुत्र राम भरत तिवारी निवासी सोनी हरलाल थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा के रूप में हुई है। बताया कि इन आरोपियों को सरजू नगर कालोनी के पास जंगल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस सफलता में पंकज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अयोध्या के अलावा उ0नि0प्रवीण कुमार मिश्रा थाना कोतवाली अयोध्या सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

कैंट पुलिस ने 1100 ग्राम गांजा के साथ शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार

अयोध्या।बीती रात एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को 1100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है।पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।इस संबंध मे थानाध्यक्ष कैंट संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को रात्रि गश्त और संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी।इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी बिंदू कुमार अग्रवाल (54 वर्ष), निवासी दालमंडी फतेहगंज, थाना कोतवाली नगर, अयोध्या को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है।उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आयुध अधिनियम तथा चोरी के माल से संबंधित धाराओं में पहले से 15 मुकदमे दर्ज हैं।इससे पहले भी वह कई बार मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है।इस गिरफ्तारी मे प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह के अलावा उपनिरीक्षक एवं चौकी प्रभारी हसनू कटरा रणजीत सिंह,हेड कांस्टेबल ज्ञान प्रकाश यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल अजीत गुप्ता तथा आरक्षी चालक राहुल वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

समेकित जन कल्याण एवं जनजागरूकता अभियान के तहत चल रहा अभियान

अयोध्या।केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान के अंतर्गत दिनांक 05 जून से दिनांक 21 जून के,प्रदेश में समेकित जन कल्याण एवं जनजागरुकता अभियान का संचालन के क्रम मे श्रम प्रवर्तन अधिकारी अयोध्या के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अभियान कार्यक्रम चलाया गया।इसी के तहत यश पैका, यश नगर, अयोध्या कारखाना में अमित कुमार मिश्रा, उप श्रमायुक्त ने श्रम प्रवर्तन भूपेंद्र, गौरव एवं सत्येंद्र प्रताप के साथ अभियान कार्यक्रम के क्रम में मौके पर यश पैका, कारखाना, अयोध्या के प्रबंधक गौतम घोष एवं सुहेल ने वहां पर मौजूद लोगो को प्रोत्साहित किया।इस मौके पर उन्होंने कारखाना में प्रोजेक्ट 04 के तहत निर्माणाधीन भवन में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उ० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार, श्रमिक पंजीकरण, पात्र श्रमिकों को योजनाओं में आवेदन हेतु प्रेरित किया।संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत पंजीकरण करवाये जाने हेतु कार्यरत श्रमिकों एवं सेवायोजको को प्रोत्साहित किया।साथ ही नवीन श्रम संहिताओं के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु सेवायोजकों के साथ संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में प्लेटफॉर्म वर्कर्स का ई–श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर श्रमिकों को ओ.आर.एस. घोल एवं अन्य पेय पदार्थ का वितरण किया गया।हीट वेव से बचाव हेतु श्रमिकों के साथ–साथ सेवायोजको को भी पर्याप्त निर्देश प्रदान किए गए।

एसएसपी डाक्टर ग्रोवर ने बीकापुर कोतवाली क्षेत्र मे कौछा बाजार अस्थाई रूप से पुलिस चौकी खोलने के जारी किये आदेश

अयोध्या ।जनपद अयोध्या में कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग को सुदृढ़ एवं सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत एसएसपी डा0 गौरव ग्रोवर ने कोतवाली बीकापुर अन्तर्गत अस्थाई नवीन चौकी कौछा बाजार बनाये जाने का आदेश पारित किया। चौकी कौछा बाजार क्षेत्र के तहत आने वाले ग्रामों में शेरपुर पारा, बेला ताजपुर, मरूई सहाय सिंह, ग्यासुद्दीनपुर, कोडरा, मुसलमीन, शिवतर, करौंदीमाफी, गीजा, हरिहरपुर, कोडरा ब्रह्मनान, रजौरा, देवापुर, बढनपुर, सरायखर्गी, सफीपुर, कादीपुर, वासुपुर, असरेवा, मोहम्मदपुर, हृदयीपुर, मौरांवा, विश्नोहरपुर, सोनवर्षा मुसलमीन, अमावां, पूरे वंशवन,असकरपुर, मजरूद्दीनपुर, भग्गूजलालपुर, बल्लीपुर, सहजपुर, डेहरियावां, सैनपुर, सेंधूतारा, मुमारिचनगर, कोछा बाजार शामिल रहेंगे।

'जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' बुधवार को जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2026 की प्रथम पाली की लिखित परीक्षा के दौरान श्री वेणी माधव विद्यापीठ बा0इ0का0 तथा आर्य कन्या पाठशाला इ0का0 बड़ा चौराहा में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया।

जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु बनाए गए हेल्प डेस्क, प्रतीक्षा स्थल तथा सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा अवधि में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखी जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सजगता से करने के निर्देश दिए।

विपक्ष सत्ता पाने की बेचैनी में लगा रहा ऐसा आरोप – धर्मवीर प्रजापति

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बुधवार को प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति अयोध्या पहुंचे।इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर दान राशि चोरी के आरोपों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब दिया।उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता पाने की बेचैनी में ऐसे आरोप लगा रहा है।कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या आकर विकास कार्य देखने की सलाह दी।धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अयोध्या की दिव्यता और भव्यता सिर्फ भारत मे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है।उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर वास्तविक स्थिति देखने की बात कही।कहा कि दान राशि मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है।मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सत्ता के लिए ऐसा कह कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि जनता सपा सरकार का दौर देख चुकी है, जब प्रदेश में जातिवाद, माफियाराज, दंगे और कर्फ्यू जैसी स्थितियां थीं।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक प्रिया के साथ महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या। बुधवार को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक प्रिया के साथ जिला महिला अस्पताल ,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक

किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें।जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर महिला होमगार्ड प्रीतू मौजूद रही।

अब साइबर क्राइम की परीक्षा पास करने पर ही मिलेगी थानेदारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। थाने की कमान संभालने से पहले इंस्पेक्टर और दरोगा को साइबर क्राइम की परीक्षा देनी होगी। बढ़ते साइबर अपराध और उसे हल करने में सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया। एक माह के प्रशिक्षण की शुरुआत जुलाई से होगी। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्य और तकनीकी जांच की बारीकियां सिखाई जाएंगी।

एमएमएमयूटी के साइबर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में 6,834 साइबर शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 5,182 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। साइबर अपराधियों ने 27.49 करोड़ रुपये की ठगी की, जबकि पुलिस केवल 9.77 करोड़ रुपये ही फ्रीज और रिफंड करा सकी। वर्ष 2026 (अप्रैल तक) में 2,767 मामलों में 10.73 करोड़ की ठगी हुई, जिसमें 3.62 करोड़ रुपये वापस कराए गए। यह राशि ठगी गई रकम की 30 फीसदी भी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश थाना और चौकी प्रभारी साइबर अपराध की तकनीकी जानकारी से वंचित हैं, जिसके कारण कई मामलों को साइबर थाने ट्रांसफर करना पड़ता है। इंस्पेक्टर व दरोगा को थाना प्रभारी बनने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा और परीक्षा पास करनी होगी। इसके तहत हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो एनालिसिस, पासवर्ड रिकवरी और साइबर सबूत जुटाने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।

'फीनिक्स यूनाइटेड में कार्टून नेटवर्क के किरदारों से बच्चों की छुट्टियां बन रही मजेदार'

'लखनऊ। गर्मी की छुट्टियों के बीच फीनिक्स यूनाइटेड, आलमबाग में आयोजित कार्टून नेटवर्क मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बच्चों और परिवारों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। पिछले दो वीकेंड्स में बच्चों ने अपने पसंदीदा कार्टून किरदारों से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और कई यादगार पल बिताए। 30 और 31 मई को टॉम एंड जेरी ने बच्चों का खूब मनोरंजन किया। दोनों दिनों में बच्चों और उनके अभिभावकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। 6 और 7 जून को क्रिस एंड क्लार्क के साथ हुए मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम को भी बच्चों का शानदार साथ मिला। बच्चों ने अपने पसंदीदा किरदारों के साथ समय बिताया और उनकी मौजूदगी का भरपूर आनंद लिया। अब इस सीरीज का अंतिम स्टेज 13 और 14 जून को आयोजित किया जाएगा, जब टीन टाइटन्स गो के लोकप्रिय किरदार फीनिक्स यूनाइटेड पहुंचेंगे। दोनों दिन दोपहर 3 बजे, शाम 5 बजे और शाम 7 बजे खघस मीट एंड ग्रीट सत्र होंगे, जहां बच्चों को अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और मजेदार पल बिताने का मौका मिलेगा। पूरे प्रोग्राम के दौरान फीनिक्स यूनाइटेड बच्चों और परिवारों के लिए एक ऐसी जगह बन गया है, जहां खरीदारी के साथ–साथ मनोरंजन और साथ बिताए गए खास पलों का भी आनंद लिया जा सकता है। फीनिक्स मिल्स के रिटेल डायरेक्टर (नॉर्थ) श्री संजीव सरीन ने कहा, "हमें खुशी है कि कार्टून नेटवर्क मीट एंड ग्रीट के माध्यम से बच्चों और परिवारों क्वालिटी समय बिताने का अवसर मिल रहा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। हमें उम्मीद है कि टीन टाइटन्स गो के साथ होने वाला प्रोग्राम भी बच्चों के लिए यादगार रहेगा।"

छत के पास से गुजर रही एलटी लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत

गोरखपुर, (संवाददाता)। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के जंगल मठिया गांव में सोमवार शाम महिला की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, रीता देवी (45) पत्नी राजकुमार शाम को अपने घर की छत पर गई थीं। इसी दौरान छत के समीप से गुजर रही एलटी लाइन की चपेट में आ गईं, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गईं। परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल उपचार के लिए एम्स लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक चौरीचौरा वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मौत करंट लगने से हुई है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जीडीए का कर्मचारी बताकर 2.50 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। मानबेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) का पत्र देकर आवास के नाम पर 2.50 लाख रुपये की ठगी के आरोपी विजय प्रताप को पुलिस ने क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्वयं को जीडीए कर्मचारी बताता था। आरोपी की पहचान सहजनवा थाना क्षेत्र के भरपुरवा भीटीरावत निवासी विजय प्रताप के रूप में हुई है। उसके कब्जे से फर्जी आवंटन पत्र भी बरामद किया गया है।

अजय नगर, रसूलपुर वार्ड नंबर 55 निवासी असगर अली ने सदर सांसद को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी मुलाकात विजय प्रताप से हुई थी, जिसने खुद को जीडीए का कर्मचारी बताते हुए मानबेला में आवास दिलाने का आश्वासन दिया। इसके एवज में उसने 2.50 लाख रुपये की मांग की। पीड़ित के अनुसार, अलग–अलग तिथियों में उनके साले की ओर से ऑनलाइन माध्यम से धनराशि भेजी गई। इसके बाद आरोपी ने जीडीए के नाम से फर्जी आवंटन पत्र तैयार कर सौंप दिया और जल्द आवास आवंटित होने का भरोसा दिलाया। शिकायत में यह भी आरोप था कि आरोपी ने उपाध्यक्ष के नाम पर भी अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। बाद में जब आवंटन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। विरोध पर आरोपी ने गाली–गलौज करते हुए धमकी दी थी। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

देश को आजाद कराने में अखबारों की मुख्य भूमिका

प्रयागराज, (संवाददाता)। 21वीं सदी की पीढ़ी अखब्बारों से दूर हो रही है। हमारे समय में सामान्य ज्ञान बेहतर करने के लिए अखब्बार पढ़ब्ना जरूरी हुआ करता था। आज अखब्बार और मीडिया भी बिल्कुल बदल गया है। यह बात पूर्व अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि आज का मीडिया पिज्जा और बर्गर की तरह हो गया है। अजीब– अजीब की तरह खब्बरें खघस तौर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। शायद इस वजह से भी लोग मीडिया से दूर हो रहे हैं। 1947 से पहले देश को आजादी दिलाने में अखब्बारों का मुख्य योगदान रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडी सेंटर के कोआर्डिनेटर डॉ. धनंजय चोपड़ा ने कहा कि इलाहाबाद ही ऐसा शहर है, जिसने महात्मा गांधी तक को पत्रकार बना दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता से 'उदन्ड मार्त्तण्ड' अखब्बार शुरू करने वाले पं. जुगल किशोर शुक्ल हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर के ही रहने वाले थे। वरिष्ठ पत्रकार लईक रिजवी ने कहा कि देश का पहला उर्दू अखब्बार इलाहाबाद से ही मुंशी सदासुख लाल ने 'बुद्धि प्रकाश' से निकाली थी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।